(1)

प्रेस नोट

बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब (Tech Hub) के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी व फिनटेक सिटी की स्थापना हेतु कार्य योजना के निर्माण तथा उसके कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण करने के लिए शीर्ष समिति के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

(2)

प्रेस नोट

बिहार को न्यू एज इकोनॉमी अंतर्गत एक 'वैश्विक–बैक एंड–हब' एवं'ग्लोबल वर्क प्लेस' के रुप में अगले पाँच वर्षो में स्थापित करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्य योजना के निर्माण तथा उसके कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण करने के लिये शीर्ष समिति के गठन की स्वीकृति के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

(3)

प्रेस नोट

बिहार के प्रतिभाशाली उद्यमियों एवं युवाओं को राज्य अंतर्गत स्टार्ट अप एवं अन्य न्यू एज इकोनॉमी प्रक्षेत्र के रोजगारोन्मुखी गतिविधियों को विस्तारित/प्रोत्साहित करने हेतु कार्य योजना के निर्माण करने एवं उसके कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण करने के लिए शीर्ष समिति के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना

(4)

बिहार सरकार
सूचना प्रावैधिकी विभाग
प्रेस नोट

बिहार राज्य को कृत्रिम बुद्धिमता (Artificial Intelligence) के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करने हेतु बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन (Bihar Artificial Intelligence Mission) की स्थापना की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार सरकार नये–नये तकनीकों का समावेश कर नवाचार के माध्यम से राज्य के विकास हेतु कृत संकल्पित है। वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमता (Artificial Intelligence) सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से एक परिवर्तनकारी तकनीक के रूप में स्थापित हो रही है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि शोध, नवाचार एवं इस क्षेत्र के अग्रणी उद्योग एवं संस्थाओं का सहयोग प्राप्त कर राज्य को कृत्रिम बुद्धिमता (Artificial Intelligence) जैसे वैश्विक परिवर्तनकारी क्षमता रखने वाले क्षेत्र में बिहार राज्य एक अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित हो जिससे राज्य के सामाजिक, आर्थिक एवं क्षेत्रीय विकास को गति मिल सके।

2. **योजना के प्रमुख लाभ :**

- ए०आई० एवं उसके उपयोग से संबंधित नीति का निर्धारण तथा संस्थानीकरण संभव हो सकेगा ।
- इस प्रक्षेत्र के अग्रणी उद्योगों/संस्थानों की सहभागिता प्राप्त करने के उद्देश्य से राज्य में ए०आई० पारिस्थितिकी का निर्माण किया जायेगा।
- राज्य में ए०आई० से संबंधित उत्कृष्टता केंद्रों Center of Excellence (CoE) की स्थापना किया जायेगा।
- कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, शासन–व्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, नगर विकास, परिवहन एवं उद्योग, लोक सेवा प्रदायगी आदि क्षेत्रों में ए०आई० से संबंधित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार संभव हो सकेगा।
- अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर शोध, पेटेंट तथा उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा।
- फेलोशीप, रेजिडेंसी तथा विशेषज्ञ विनियम कार्यक्रम के माध्यम से दीर्घकालिक प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा।

- उत्तरदायी एवं ओपन डाटा को बढावा दिया जायेगा ताकि पारदर्शिता तथा नागरिकों का विश्वास सुनिश्चित हो सके।
- राज्य के तकनीकी संस्थानों के माध्यम से शिक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा। जिससे कि ए०आई० आधारित प्राद्यौगिकी अनुकूलन को बढावा मिले।
- Responsible AI Ecosystem के विकास से संबंधित नियमों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

(5)

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

बिहार, पटना

।। प्रेस नोट ।।

राज्य के प्रमुख शहरों की बढ़ती जनसंख्या, मास्टर प्लान आधारित विकास की अपरिहार्यता एवं भविष्य के जनसंख्या दबाव, शहरों की बढ़ती आवश्यकताओं को देखते हुए राज्य में नियोजित, पर्यावरण–सम्मत एवं आधुनिक टाउनशिप के विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य में सुनियोजित एवं गुणवत्ता युक्त शहरी विकास हेतु 11 शहरों यथा–09 प्रमंडलीय मुख्यालय शहर, सोनपुर एवं सीतामढ़ी (सीतापुरम) में नये सैटेलाईट टाउनशिप/ग्रीनफिल्ड टाउनशिप के विकास के सैद्धान्तिक सहमति तथा प्रस्ताव तैयार करने की स्वीकृति प्रदान की गयी, जिससे राज्य में सैटेलाईट टाउनशिप/ग्रीनफिल्ड टाउनशिप का विकास किया जाएगा।

(अभय कुमार सिंह)
सरकार के सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

(10)

बिहार सरकार
गन्ना उद्योग विभाग

प्रेस विज्ञप्ति
सूचना

राज्य में नये चीनी मिलों की स्थापना एवं पुराने बंद पड़े चीनी मिलों के पुनरूद्धार से संबंधित नीति निर्धारण/कार्य योजना हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया, जिससे नई चीनी मिलों की स्थापना/बंद पड़ी चीनी मिलों का पुनरूद्धार हो सकेगा तथा किसानों को उच्चतर रिटर्न एवं रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सकेगा।

(नर्मदेश्वर लाल)
प्रधान सचिव।

Santokh-I